लोक प्रशासन (प्रश्न-पत्र II) PUBLIC ADMINISTRATION (Paper II)

निर्धारित समय : तीन घण्टे

Time Allowed: Three Hours

अधिकतम अंक : 250 Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें।

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are EIGHT questions divided in TWO SECTIONS and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिये : Answer the following in about 150 words each :

भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय प्रशासन के लिये आदर्शों तथा मूल्यों की रूपरेखा प्रदान करती है। विवेचना कीजिये।

 $10 \times 5 = 50$

1.

1.(a)

HXS-B-PBAD

The Preamble to the Constitution of India provides a foundational framework of ideals and values for the Indian administration. Discuss.
परीक्षण कीजिये कि किस सीमा तक संविधानवाद के आदर्श के रूप में 'सीमित शक्तियों द्वारा शासन' भारत में एक कार्यात्मक वास्तविकता रहा है।
Examine the extent to which the ideal of Constitutionalism as 'government by limited powers' has been a functional reality in India.
सुशासन के क्रियान्वयन में लालफीताशाही एक प्रमुख अवरोध है। टिप्पणी कीजिये।
Red-tapism is a major obstacle to the implementation of 'good governance'. Comment. 10 संसदीय व्यवस्था में स्पीकर की भूमिका एवं स्थिति तटस्थता पर स्पीकर की अवस्थिति पर आधारित है। टिप्पणी कीजिये।
The role and status of the Speaker in parliamentary system have their foundation in the Speaker's stance on neutrality. Comment.
केन्द्र सरकार वर्तमान स्थानीय सरकारी सेवाओं की बढ़ती संख्या को प्रशासित करने के लिये रणनीतियों को विकसित एवं व्यवहारिक बनाने का कार्य स्थानीय पहलों तथा स्वविवेक को दरिकनार करते हुये करती है। परीक्षण कीजिये।
The Union government develops and practices strategies to administer increasing number of existing local government services by sidelining local initiatives and discretion. Examine. 10
कौटिल्य ने राज्य तथा इसके लोगों के संरक्षण, कल्याण एवं समृद्धि को अवधारित किया जो कि एक शासक का अन्तिम सरोकार होना चाहिये। इस सन्दर्भ में समसामयिक भारत में सुशासन, जवाबदेयता तथा न्याय पर कौटिल्य के प्रभाव के महत्व का विवेचन कीजिये।
Kautilya envisages protection, welfare and prosperity of the State and its people as the utmost concern of a ruler. In this context, discuss the significance of Kautilya's emphasis on governing, accountability and justice in contemporary India.
भारत में जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधिकारी एक अति महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी है। उपर्युक्त कथन के सन्दर्भ में भारत में समन्वित विकासात्मक प्रशासन लाने हेतु जिलाधिकारी के बहुआयामी उत्तरदायित्वों की विवेचना कीजिये।
District Collector is the most important functionary in district administration in India. In light of the above statement, discuss the multidimensional responsibilities of District Collector in effecting coordinated developmental administration in India.
राज्यपाल की भूमिका एक सक्रिय राजनीतिज्ञ की अपेक्षाकृत एक दूरदर्शी परामर्शदाता, मध्यस्थ तथा विवाचक की होती है। इस सन्दर्भ में भारत की राज्यीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण कीजिये।
The role of the Governor is of a sagacious counsellor, mediator and arbitrator rather than that of an active politician. In this context, examine the role of the Governor in state politics in India.
भर्ती सम्पूर्ण लोक कार्मिक संरचना की आधारशीला है और यह उत्कृष्ट को आकर्षित करने की समस्या पर केन्द्रित है। एक श्रेष्ठ भर्ती व्यवस्था के अनिवार्य तत्वों की विवेचना कीजिये।
Recruitment is the cornerstone of the whole public personnel structure and it revolves around the problem of attracting the best. Discuss the essential elements of a good recruitment system.

	44 0 00 00 00 44
3. (b)	परम्परागत रूप से संरचित प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने अपनी उपयोगिता खो दी है। विवेचना कीजिये कि कैसे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सामने आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिये वर्तमान सरकारी ढाँचे का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन एवं पुन:रचना हेतु प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। Traditionally structured administrative systems have outlived their utility. Discuss as how administrative reforms can revamp, restructure and redesign the existing governmental structure to meet the new challenges faced by the Indian administrative set-up.
3. (c)	अर्थ व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के वृहद स्तर पर निजीकरण की सरकारी नीति भारत के आर्थिक स्वास्थ्य की
	The government policy of large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the key sectors of economy may are the large scale privatization of the large scale privatization of the key scale privatization of the large scale privatiz
4. (a)	एक संवैधानिक आदेश प्राप्त निकाय के रूप में वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद का केंद्र बन चुका है। संघ और राज्यों के मध्य संसाधनों के न्यायपूर्ण तथा समान सहभाजन को आश्वस्त करने में वित्त आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।
	As a constitutionally mandated body the Finance Commission stands at the centre of fiscal federalism. Evaluate the role of Finance Commission in ensuring just and equitable resource sharing among the states and the union.
4. (b)	लोक सेवाओं की वर्तमान बाजार उपागमों ने परम्परागत और राज्य प्रायोजित लोक सेवा मूल्यों को गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत की है। भारतीय प्रशासन के सन्दर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिये।
	Recent market approaches to public services present serious challenges to traditional and state-sponsored public service values. Evaluate the statement in the context of Indian administration
4. (c)	राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत बनावट के लिये एक प्रमुख खतरा है। टिप्पणी कीजिये।
	The increasing criminalization of politics is a major threat to the basic fabric of Indian democracy. Comment.
	खण्ड 'B' SECTION 'B'
5.	निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिये।
	Answer the following in about 150 words each: ग्रामीण विकास की कोई भी रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह उपयुक्त पंचायती राज
5.(a)	गंखाओं से अनुपरित नहीं हो । इस कथन का परीक्षण कीजिय ।
	No rural development strategy can succeed unless it is complemented by appropriate
5. (b)	नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिये किया गया है।
	NITI Aayog has been constituted to implement the goal of co-operative federalism. Discuss.
5. (c)	उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता सुशासन के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। भारतीय प्रशासन के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये।
	Responsibility and accountability are two major goals of Good Governance. Discuss the statement in the context of Indian administration.
5. (d)	अत्यंत महत्त्व के सामरिक मुद्दों पर निर्णय निर्माण में भूमिका के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय अपने आप में

The Prime Minister's Office has become a powerful institution in itself by virtue of its role in decision-making on strategic issues of utmost importance. Examine the statement.

एक सशक्त संस्था बन गया है । इस कथन का परीक्षण कीजिये ।

5.(d)

5. (e)	सुनियोजित और उद्देश्योन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में सिविल सेवा व्यवस्था की रीढ की हड्डी है। इस कथन का परीक्षण कीजिये।
	Well planned and goal oriented training programmes are the backbone of the civil service system in India. Examine the statement.
6. (a)	संसद/राज्य विधायिकाऐं बजट प्रस्तावों की प्रभावी संवीक्षा को आश्वस्त करने में असफल रही हैं। बजट प्रस्तावों की प्रभावी संवीक्षा में बाधित करने वाले कारकों को चिन्हित कीजिये।
	Budget proposals in the Parliament / State Legislatures fail to ensure their effective scrutiny. Identify the factors which constrain effective scrutiny of the budget proposals.
6. (b)	73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए शासन के तृतीय स्तर को अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने से था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये कि यह लक्ष्य किस सीमा तक वास्तविकता में रूपांतरित हुआ।
	73rd and 74th Constitutional Amendment Acts aimed at making the third tier of government more powerful and effective for democratic decentralization. Critically examine the extent to which this goal has been transformed into reality.
6. (c)	सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अन्वेषण नहीं कर पाने की न्यायायिक क्षेत्राधिकार सीमाओं के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बाधाग्रस्त है। विवेचना कीजिये।
	National Human Rights Commission is handicapped by its jurisdictional limitations of not being able to investigate the cases of violation of human rights by the armed forces. Discuss.
7.(a)	समकालान नगरवाद नगर योजना तथा प्रबंधन सरोकारों के विविध रूपों के समाकलन का पक्ष समर्थन करता है। भारत में नगर विकास के आलोक में उक्त कथन की विवेचना कीजिये।
t ,	Contemporary urbanism advocates the integration of diverse modes of urban planning and management concerns. Discuss the above statement in light of urban development in India.
7.(b)	ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन के बहुमुखी विकास को सुगम बनाने के लिये तैयार किये गये हैं। इस संदर्भ में भारत में कुछ मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका की विवेचना कीजिये। Rural development programmes are designed to facilitate multifaceted growth of rural poor. Evaluate the role of some key rural development programmes in India in this context.
7.(c)	भारत में पुलिस-जन संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। पुलिस और जनता के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
	Police-public relations in India need to be improved. Suggest measures to strengthen relations between police and public.
8.(a)	विगत दो दशकों में भारत की आपदा प्रबन्धन की लोकनीति बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों पर केन्द्रित होने से हटकर आपदा के समग्र प्रबन्ध की ओर स्थानान्तरित हो गई है। विश्लेषण कीजिये। In past two decades India's public policy on Disaster Management has shifted its focus from rescue, relief and rehabilitation efforts to holistic management of line.
8.(b)	ंकुशल सुदृढ़ीकृत राज्य' की सांस्थानिक विरासत ने भारत में सुधार पश्चात् आशाओं को प्रभावित किया है। भारत में आर्थिक सुधारों के आलोक में इस कथन की लगला की निर्माण
9 (a)	The institutional legacy of 'well-entrenched state' affected the post-reforms promises in India. Explain the statement in the light of economic reforms in India.
8.(c)	क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में सिविल सेवा अपने तटस्थ और अनामित चरित्र को खो रही है ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए । Do you agree with the view that the civil service in India is losing its neutral and
	anonymous character? Argue your case.